(c) No, Sir, The complaints are being attended to properly.

(d) and (e) The questions do not arise in view of reply at (a) and (c) above.

दिल्ली में गांवों का शहरीकरण

770. **श्री रामजीलालः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) इस समय दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए दिल्ली के गांवों को शहरीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ग) अब तक शहरीकृत गांवों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शहरी करण किए जाने के लिए शेष गांवों का ब्यौरा क्या है?

शहरीकार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली में गांवों का शहरीकरण जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता है।

(ग) एम सी डी, एन डी एम सी तथा दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शहरीकृत गांवों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

एम सी डी	135 गांव
दिल्ली छावनी बोर्ड	6 गांव
एनडीएमसी	1 गांव

(घ) एम सी डी और डीडीए ने सूचित किया है कि क्रमशः 15 तथा 68 गांवों को शहरीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

दिल्ली में नर्सिंग होमों के लिए भूमि

771. **श्री रामजीलालः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में नर्सिंग होमों के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरे सहित ऐसी रियायत देने के क्या कारण हैं;

(ग) समाज के गरीब वर्ग के लिए अब तक 25 प्रतिशत पलंग उपलब्ध न कराने वाले नर्सिंग होमों के नाम क्या-क्या है; और

(घ) समाज के गरीब वर्ग के लिए प्रति वर्ष 25 प्रतिशत पलंग उपलब्ध न कराने वाले नर्सिंग होमों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डीडीए ने सूचित किया है कि दिल्ली में नर्सिंग होम के लिए प्लाटों का आबंटन खुली नीलामी के माध्यम से किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

"सब के लिए आवास" हेतु निर्धारित लक्ष्य

772. **श्री लाला लाजपत रायः क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 तक "सब के लिए आवास" कराने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या वर्ष 2000 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और मुम्बई 'दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद में आवासीय समस्या के संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) शासन के राष्ट्रीय एजेण्डा के भाग के रूप में सरकार का लक्ष्य प्राप्त वर्ष 2 मिलियन अतिरिक्त आवास यूनिटें उपलब्ध कराने का है। इसमें से 7 लाख यूनिटें शहरी क्षेत्र में होंगी।

(ख) 12.02.99 तक 2, 15,769 यूनिटों की मंजूरी दी गई है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रगति की हाल ही में की गई समीक्षा से पता चलता है कि 7 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य तकरीबन पूरा हो जाएगा। तथापि ये अधिकांशतः राज्य सरकारों द्वारा हुडको को समय पर परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। भारत सरकार ने मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई तथा हैदराबाद के बारे में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।